अध्याय - 3
मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली

हम पढ़ेंगे

17.1 मुद्रा का परिचय एवं विकास
17.2 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य
17.3 वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाएँ
17.4 प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ
17.5 बैंकों के प्रकार

17.1 मुद्रा का परिचय एवं विकास

'मुद्रा' शब्द अंग्रेजी के 'Money' का हिन्दी रूपान्तरण है। Money (मनी) शब्द लैटिन भाषा के 'Moneta' (मोनेटा) शब्द से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो (Goddess Juno) को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। प्रारम्भ में रोम में सिक्के की ढलाई का काम स्वर्ण की देवी जूनो के पवित्र मंदिर में ही होता था। लैटिन भाषा में मुद्रा को पैक्यूनिया कहते थे जो पैकस (Pecus) शब्द से बना है, जिसका अर्थ पशुधन है। आज जो मुद्रा का स्वरूप देखने को मिलता है, उसके विकास का एक लम्बा इतिहास है। प्राचीन युग का मनुष्य भी अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता था। फलतः उसने अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारम्भ किया। इसे 'वस्तु विनिमय' के रूप में जाना जाता है। अदला-बदली की यह प्रणाली काफी समय तक चलती रही। समय के साथ-साथ वस्तु-विनिमय प्रणाली की अनेक कठिनाईयाँ सामने आईं। इस प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे एवं बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार हो। प्रारम्भ में गाय, बकरी, सीप, मछली के काटों, जानवरों की खाल, हाथी दाँत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया। किन्तु इस व्यवस्था से भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आई, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, संचय की कठिनाई आदि। इससे धातुओं के उपयोग की प्रेरणा मिली। फलतः धातु का सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा, जिससे अनेक समस्याएँ हल हो गईं। राजा एवं महाराजाओं ने जालसाजी को रोकने के लिये इन सिक्कों की तौल, आकार, रंग-रूप आदि को निर्धारित किया तथा इन सिक्कों की प्रमाणिकता के लिये उन पर सरकार की मुहर लगाई जाने लगी। सोना, चाँदी, तांबा आदि धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में किया गया।

समय के साथ-साथ धातु मुद्रा की कठिनाईयाँ सामने आने लगीं। फलतः बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूपों में हुआ, जैसे लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा आदि। केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ-साथ चैक, हुण्डी, ड्राफ्ट के रूप में साख मुद्राओं का विकास हुआ। वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं ए.टी.एम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में हम जो मुद्रा देख रहे हैं उसका एक लम्बा इतिहास है। इसे निम्न चार्ट द्वारा भी समझा जा सकता हैं -

ए.टी.एम. (ATM)

ए.टी.एम. अंग्रेजी भाषा के शब्द Automated Teller Machine का संक्षिप्त रूप है। जो वर्तमान में बैंकिंग कार्य के लिए अत्याधिक प्रचलित हो गया है। यह कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी रहती है, जिस पर बैंक एकाउन्ट से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। वास्तविकता यह है कि ए.टी.एम. ने बैंकिंग कार्य को बहुत अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है।

मुद्रा का विकास क्रम

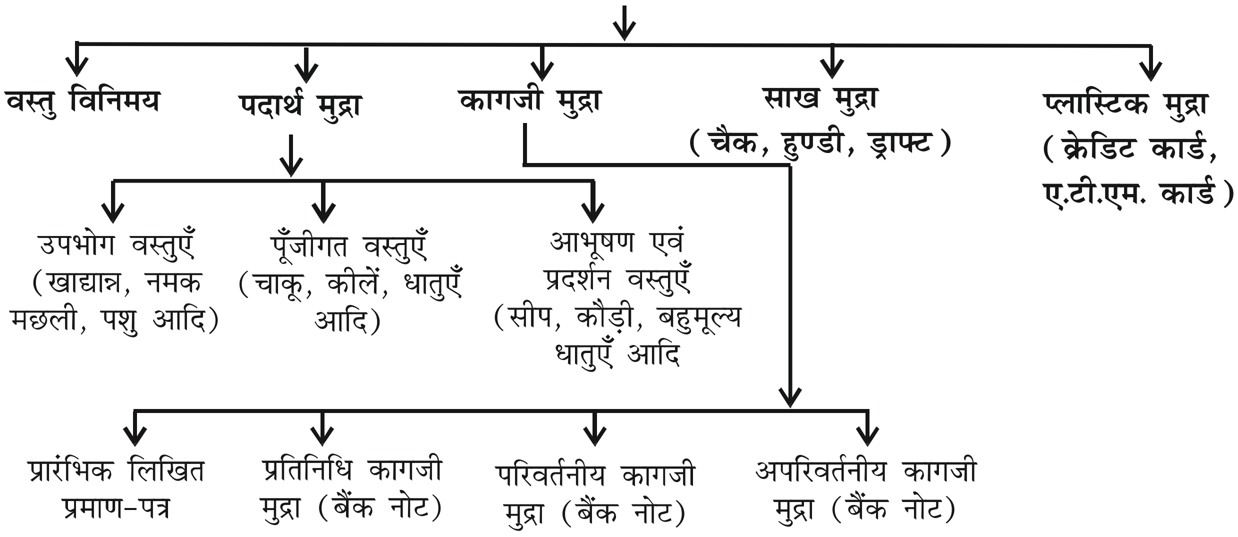

17.2 मुद्रा की परिभाषा एवं कार्य

मुद्रा के कार्य एवं प्रकृति के आधार पर विद्वानों ने मुद्रा को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। मुद्रा की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं -

प्रो. मार्शल के अनुसार ''मुद्रा में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित हैं, जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जाँच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती हैं।''

प्रो. एली के अनुसार ''मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है, जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है, जो सामान्यत: ऋण के अंतिम भुगतान में स्वीकार की जाती है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आधुनिक युग में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में अनेक कार्य करती है। मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

1. **विनिमय का माध्यम** - वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। उत्पादक अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और तत्पश्चात् प्राप्त मुद्रा के द्वारा वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है।

2. **मूल्य का मापन** - वर्तमान में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है।

3. **क्रयशक्ति का हस्तान्तरण** - मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है। किसी स्थान से वस्तुएँ खरीदने की स्थिति में उनके मूल्य का भुगतान मुद्रा द्वारा या बैंक ड्राफ्ट, चेक, मनीआर्डर आदि के द्वारा किया जाता है। बैंकों के माध्यम से रुपए को सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है।

4. **क्रय शक्ति का संचय** - मनुष्य स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है। मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए रखना सरल हो गया है। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस में रुपये जमा करके क्रयशक्ति का संचय करना एक आम बात हो गई है।

इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार लेन-देन की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। उपभोक्ता मुद्रा के

माध्यम से ही अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। संक्षेप में, मनुष्य के जीवन में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है।

17.3 वित्तीय-प्रणाली एवं संस्थाएँ

दैनिक जीवन में व्यक्तियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए-पैसों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योग-धन्धों एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों के संचालन के लिए धन की आवश्यकताएँ होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति एवं कृषक सभी को धन उधार लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हमारी आय, अपनी आवश्यकता से अधिक होती है, तब उसे सुरक्षित रूप से रखने और उससे ब्याज के रूप में आय कमाने के लिए भी वित्तीय संस्थाओं की जरुरत होती हैं। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएँ हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रुप में अपने पास रखती है और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है, उन्हें ऋण के रूप में उधार देती है। अतः जमा के रूप में धन एकत्रित करने और ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली के रुप में जाना जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है।

एक वित्तीय प्रणाली में धन का लेन-देन करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय संस्थाएँ कहा जाता है। ये संस्थाएँ बचतों को आकर्षित करने के लिए जमाकर्ताओं को ब्याज देते है और उधार लेने वाले व्यक्ति से ब्याज वसूल करते हैं। धन के लेन-देन की यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। देश में कार्यरत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है, प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएँ और द्वितीय, निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं का संचालन जन-साधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में सन् 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया। व्यापारिक बैंकों के साथ-साथ बीमा कम्पनियाँ एवं अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथों में होता है, जैसे- जमींदार, चिट-फंड आदि। वर्तमान में अनेक व्यापारिक बैंक एवं बीमा कम्पनियाँ भी निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं।

17.4 प्रमुख वित्तीय-संस्थाएँ

भारत में कार्यरत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्थाएँ निम्नलिखित हैं -

बैंक - आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे जरूरतमन्दों को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में सभी आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंकों का कार्य मुद्रा के लेन देन के साथ-साथ साख का निर्माण करना भी है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि ‘बैंक मुद्रा एवं साख का व्यवसाय करने वाली संस्था है’। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया जैसी अनेक बैंक कार्यरत हैं।

सन् 1991 के बाद निजी क्षेत्र में अनेक बैंक स्थापित किए गए है। उदाहरणार्थ - आई.सी.आई.सी.आई (ICICI) बैंक , एच.डी.एफ.सी (HDFC) बैंक, यू.टी.आई. (UTI) बैंक, इन्डस (INDUS) बैंक आदि निजी क्षेत्र की बैंक हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र में बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है।

बीमा कम्पनियाँ – बीमा जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है। मानव जीवन के साथ-साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। बीमा कम्पनियाँ प्राप्त धनराशि का विभिन्न उत्पादक कार्यों में निवेश करती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास होता है। सन् 1991 से बीमा का क्षेत्र भी निजी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है।

साहूकार – साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। साहूकार दो प्रकार के होते हैं। (अ) कृषक साहूकार या जमींदार तथा (ब) व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं। लेकिन धनवान होने के कारण, धन उधार देने का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। साहूकारों के कार्य करने का तरीका बहुत सरल होता हैं। ये अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह उत्पादन व उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ऋण जमानत लेकर व बिना जमानत लिए दोनों प्रकार के होते हैं।

साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम हैं। इसका प्रमुख कारण इनकी दोषपूर्ण कार्य-प्रणाली है जिसमें (अ) ऊँची ब्याज दर, (ब) अग्रिम ब्याज, (स) हिसाब में गड़बड़ी, (द) बेगार कराना आदि सम्मिलित हैं। अतः सरकार ने साहूकारों पर नियन्त्रण लगा दिया है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

जमींदार – इस प्रथा का प्रारम्भ 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में किया था। जमींदार बड़े भू स्वामी होते थे। इनका कार्य किसानों से लगान वसूल करना था। ये किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे। जमींदार आवश्यकता पड़ने पर किसानों को उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋण भी दिया करते थे। इनके द्वारा किसानों को दिए गये ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती थी। इनके द्वारा प्रदत ऋणों की शर्तें भी कठोर होती थी। ये ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का शोषण होता था। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया है।

स्व सहायता समूह – स्व सहायता समूह **गरीब व्यक्तियों** का एक स्वैच्छिक संगठन है। इन समूहों का गठन आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है, वह खाता समूह के नाम होता है। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 होती है।

प्रायः समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुँच बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। अतः समूह सदस्यों को बचत की ऐसी विधि सिखाता है, जो सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त है। समूह सदस्यों को कम ब्याज दर पर आसानी से छोटे ऋण उपलब्ध कराता है। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समूह की बैंकिंग सम्बन्धित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है।

देश में स्व सहायता समूह महिलाओं का हो सकता है, पुरूषों का हो सकता है या फिर महिला और पुरूष दोनों का मिश्रित हो सकता है, परन्तु यह देखा गया है कि महिला स्व सहायता समूह ही अधिक सफल रहे हैं।

स्व-सहायता समूह के गठन के उद्देश्य

किसी भी स्व-सहायता समूह के गठन के निम्नलिखि उद्देश्य हो सकते है -

- सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना विकसित करना,
- सदस्यों में बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत विकसित करना,
- सदस्यों को ऋण प्रदान करके स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना,
- सदस्यों में स्वावलंबन की भावना का विकास करना,
- स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों के प्रति जागृति पैदा करना और
- सरकार, बैंक तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन आदि।

बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक

स्व-सहायता समूहों के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का एक ठोस तंत्र विकसित हुआ है। इन बैंकों में अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो बांग्लादेश के 40,000 गाँवों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1970 में मोहम्मद युनूस द्वारा की गई थी। इन ग्रामीण बैंकों ने गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कार्य के लिए मोहम्मद युनूस को सन् 2006 में नोबेल पुरूस्कार से सम्मानित किया गया।

स्व-सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाओं के लिए विस्तार में बांग्लादेश को बहुत अधिक सफलता मिली है। भारत में भी इसका विस्तार सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में एक **मोबाइल बैंक** की स्थापना की गई है। 'लक्ष्मी वाहिनी' के नाम से यह संस्था एक गाड़ी में चलते-फिरते बैंक का कार्य करती है। इसकी पूंजी एक करोड़ रु. है और यह गाँव-गाँव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिग सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

चिट-फंड - चिट-फंड योजनाओं का दक्षिण भारत के राज्यों में लम्बा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गाँवों में यह बहुत लोकप्रिय है। वहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित है। चिट-फंड भारत में पायी जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाये जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अन्तराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर, तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि की सदस्यों के बीच नीलामी की जाती। इस नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊँची बोली लगाता है, उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। इस प्रकार की चिट-फंड योजनायें किसी पंजीकृत वित्तीय संस्था या कुछ मित्र या रिश्तेदार आपस में मिलकर भी चलाते हैं। उद्देश्य में भिन्नता के साथ अलग-अलग तरह की अनेक चिट-फंड योजनाएँ देश में चल रही हैं।

17.5 बैंकों के प्रकार

1. **वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक** - व्यापारिक बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। यह बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वाणिज्य बैंकों के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब वाणिज्य बैंक कृषि विकास एवं लघु उद्योगों के विकास एवं विस्तार के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों के साथ-साथ अनेक निजी क्षेत्र के बैंक भी कार्यरत हैं।

2. **औद्योगिक बैंक** - उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली

संस्थाएँ औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्त्रोतों से पूँजी प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। भारत में औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है।

3. विदेशी विनिमय बैंक – विदेशी मुद्राओं का लेन-देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएँ विदेशों में स्थापित करती हैं, जिससे विदेशी मुद्राओं के लेन-देन का कार्य सरल हो जाता है। जैसा कि विदित है कि एक देश का निर्यातक अपनी वस्तु की कीमत अपने देश की ही मुद्रा में प्राप्त करना चाहता है। अतः एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या आती है। विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करते हैं। वर्तमान समय में विनिमय बैंक, वाणिज्य बैंकों के समान बैंकों के अन्य कार्य भी करती हैं। इसी तरह वाणिज्य बैंक भी विनिमय बैंकों के कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसे बैंक जो अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ-साथ विदेशी विनिमय का लेन-देन करते हैं, विनिमय बैंक कहलाते हैं।

4. कृषि बैंक – कृषि व्यवस्था, व्यापार तथा उद्योग-धन्धों से भिन्न होती है। अतः इसकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यापार तथा उद्योग-धन्धों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं से भिन्न होती है। यही कारण है कि किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई। कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित कृषि बैंकों द्वारा की जा रही है –

अ. कृषि सहकारी बैंक – कृषि सहकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधाएँ कम ब्याज की दर पर प्रदान करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है। इन समितियों के ऊपर केन्द्रीय सहकारी बैंक होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों को ऋण देते हैं। इन केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य सहकारी बैंकों को जब ऋण सम्बन्धी आवश्यकता होती है तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे **नाबार्ड** भी कहा जाता है, इनकी मदद करता है।

ब. भूमि विकास बैंक – भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। यह बैंक भूमि में सुधार करने, कुआँ खोदने, नलकूप लगाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रेक्टर खरीदने आदि के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण देते हैं। चूँकि इन बैंकों द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है, अतः इनका लाभ बड़े किसानों द्वारा अधिक उठाया जा रहा है।

स. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है। इन बैंकों द्वारा छोटे एवं सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों एवं छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किये जाते हैं। देश में 30 जून, 2005 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,484 शाखायें कार्यरत थीं।

4. राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक – राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई। इसे संक्षेप में नाबार्ड कहते है। यह ग्रामीण ऋण ढाँचा में एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। यह संस्था अनेक वित्तीय संस्थाओं, जैसे- राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान करती है। अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नावार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करता है।

5. रिजर्व बैंक – रिजर्व बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था होती है। इस बैंक का जनता से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। देश की मुद्रा छापने का कार्य इसी बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंक सरकार की बैंकर होती है। सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है। यह बैंक 'बैंकों की बैंक' हैं। देश के सभी बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग इसके पास रखना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर यह बैंक अन्य बैंकों को ऋण भी देती है। इसके अलावा यह देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखती है। अन्य सभी बैंकों को इसके आदेशों तथा नीतियों का पालन करना पड़ता है। भारत के केन्द्रीय बैंक को 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' के नाम से जाना जाता है।

6. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक – अन्तर्राष्टीय बैंकों के अन्तर्गत उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है। जिनकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है। इस दिशा में 1945 में दो संस्थाओं विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी।

शब्दावली

वस्तु विनिमय – एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या वस्तुओं की अदला-बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है।

मुद्रा – वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है।

पत्र मुद्रा – वह कागजी मुद्रा है जिसे, केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी किया जाता है।

परिवर्तनीय पत्र मुद्रा – जब पत्र मुद्रा, स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय होती है, तब उसे परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है।

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा – जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय नहीं होती, तब उसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है।

साख मुद्रा – जारी करने वाली संस्था के नाम के आधार पर स्वीकार किए जाने वाले कागजी प्रपत्र जैसे- चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. कार्ड आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंक – वे बैंक जिन्हें सन् 1969 एवं 1980 में सरकार ने अधिग्रहित किया। अब इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में जाना जाता है।

विदेशी विनिमय – एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना विदेशी विनिमय कहलाता है।

निजी क्षेत्र के बैंक – जिन बैंकों का स्वामित्व निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के हाथों में होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है।

नाबार्ड – इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। यह संस्था भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु दिए गए ऋणों की प्रतिपूर्ति करती है। यह ग्रामीण एवं कृषि ऋणों से संबंधित एक शीर्ष संस्था है।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए

1. मुद्रा का प्रमुख कार्य हैं –
   (i) विनिमय का माध्यम
   (ii) मूल्य संचय
   (iii) स्थगित भुगतानों का मान
   (iv) उपर्युक्त सभी
2. साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है –
   (i) औद्योगिक वित्त में
   (ii) विकास वित्त में
   (iii) कृषि वित्त में
   (iv) उपरोक्त में से कोई नहीं
3. विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है –
   (i) जमाएँ स्वीकार करना
   (ii) ऋण देना
   (iii) मुद्रा का विनिमय करना
   (iv) उपरोक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

1. एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला-बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना .... प्रणाली कहा जाता है।
2. वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थायें धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को .... देता है।
3. स्व-सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या .... होती है।
4. औद्योगिक बैंक उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन .... प्रदान करती हैं।
5. बचत बैंक लोगों की .... को एकत्रित करती हैं।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. वस्तु-विनिमय की प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी?
2. 'चिटफंड' भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित हैं?
3. बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में मुख्य अन्तर क्या हैं?
4. भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि के ऋण देता है?
5. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है?
6. देश में नोट छापने का कार्य किस बैंक द्वारा किया जाता है?
7. देश का पहला मोबाइल बैंक किस प्रदेश में स्थापित किया गया है?

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्राचीन काल में किन-किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? लिखिए।
2. साहूकारी व्यवस्था के दोषों को बताइये।
3. मुद्रा की परिभाषा दीजिए।
4. व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं?
5. वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मुद्रा के विकास पर एक लेख लिखिए।
2. स्व-सहायता समूह किसे कहते है? इसके गठन के क्या-क्या उद्देश्य हो सकते हैं? लिखिए
3. भारत में पायी जाने वाली निजी वित्तीय संस्थायें कौन-कौन सी हैं? लिखिए।
4. बैंकों के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं? लिखिए।
5. मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए।
6. कृषि को ऋण देने वाली संस्थाओं की विवेचना कीजिए।